

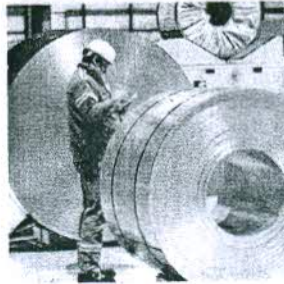
US tariffs on steel may hurt local metal industry

New Delhi: The decision to impose steep tariffs by the United States on steel and aluminium may impact the domestic metal sector, a report has said.

On March 8, 2018 US President Donald Trump imposed a 25% tariff on steel imports and 10% on aluminium.

"The decision to hike tariff on aluminium and steel by 10% and 25%, respectively made under a section 232 of American federal Act of 1962, may impact the Indian metals sector.

"(However) It would be difficult to estimate what would be the quantum of impact on Indian steel and aluminium exports consequent to imposition of tariffs on steel and aluminium, the Indian exports may become costlier and uncompetitive in the US market especially against other countries who are exempted from levy of



tariff by the US," Industry body Assocham said in its latest report 'Global Tariff War: Implications and Challenges'.

Besides, it could also affect the prices of other metals like zinc and nickel.

The US is the world's largest steel importer. In 2017, it imported 35.6 million tonne (MT) of steel.

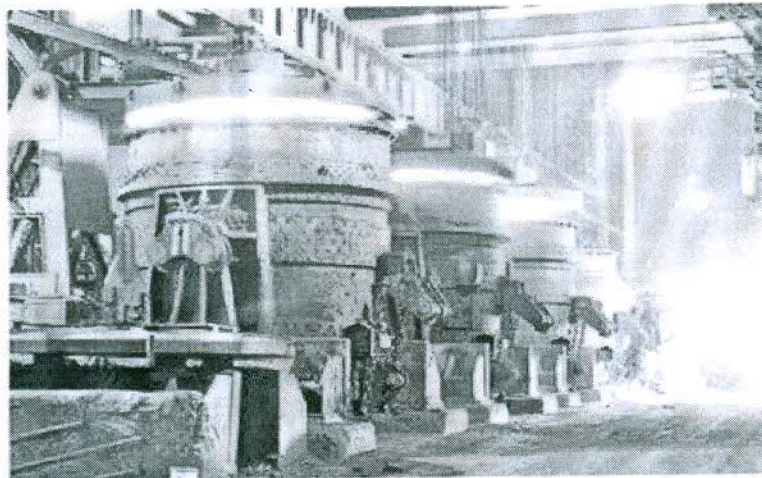
The imposition of tariffs on steel and aluminium imports into the US followed by slapping of tariffs on a wide range of Chinese imports

has thrown global trading system into disarray. The tit-for-tat approach in global trading relations is unfolding rapidly as major economies continue to impose tariffs on each other, the report said.

This could intensify and stunt global economic growth, causing greater difficulties in developing countries, including India, it noted.

Union Steel Minister Chaudhary Birender Singh had earlier said that the 25% tariff imposed by the US on steel import can 'indirectly' affect the domestic sector. "The US decision to impose 25% tariff on steel imports will have negligible direct impact (on India's export) as India's share of US Steel imports is very small as compared to other countries but there might be an indirect impact (in the form of dumping)," he had said. —PTI

'US tariffs to affect local firms'



TARIFF HIKE: US on March 8 imposed a 25 per cent tariff on steel imports and 10 per cent on aluminium.

NEW DELHI

The decision to impose steep tariffs by the United States on steel and aluminium may impact the domestic metal sector, a report has said. On March 8, 2018 US President Donald Trump imposed a 25 per cent tariff on steel imports and 10 per cent on aluminium. "The decision to hike tariff on aluminium and steel by 10 per cent and 25 cent, respectively made under a section 232 of American federal Act of 1962, may impact the Indian metals sector.

"(However) It would be difficult to estimate what would be the quantum of impact on Indian steel and aluminium exports consequent to imposition of tariffs on steel and aluminium, the Indian exports may become costlier and uncompetitive in the US market especially against other countries who are exempted from levy of tariff by the US," Industry body Assocham said in its latest report 'Global Tariff War: Implications and Challenges'.

Besides, it could also af-

US is the world's largest steel importer. In 2017, it imported 35.6 million tonnes (MT) of steel. The imposition of tariffs on steel and aluminium imports into the US followed by slapping of tariffs on a wide range of Chinese imports has thrown global trading system into disarray. The tit-for-tat approach in global trading relations is unfolding rapidly as major economies continue to impose tariffs on each other, the report said.

This could intensify and stunt global economic growth, causing greater difficulties in developing countries, including India, it noted. Union Steel Minister Chaudhary Birender Singh had earlier said that the 25 per cent tariff imposed by the US on steel import can 'indirectly' affect the domestic sector.

"The US decision to impose 25 per cent tariff on steel imports will have negligible direct impact (on India's export) as India's share of US Steel imports is very small as compared to other countries but there might be an indirect impact

सार्वजनिक इस्पात कंपनियों को करना होगा निजी इकाइयों का अनुकरण: चौधरी बीरेंद्र सिंह

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि इस्पात क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी कंपनियों की गतिविधियों का अनुकरण करना होगा। देश में कुल घरेलू उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 80 से 82 प्रतिशत है। इस्पात मंत्री ने स्टील क्षेत्र में एक वैश्विक इकाई के रूप में उभरने के लिए चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से अवसर छीनने का भी आह्वान किया। हाल में हुई बैठक में सिंह के हवाले से ब्योरे में कहा, सार्वजनिक उपक्रमों का इस्पात उत्पादन में योगदान 18 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में उन्हें निजी क्षेत्र से सीखने की जरूरत है जिनका उत्पादन में 80 से 82 प्रतिशत योगदान है। अगर भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत और प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में उभरना है, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र की कंपनी से सीखना होगा। मंत्री ने उच्च गुणवत्ता के मिश्रधातु के उत्पादन पर जोर देते हुए इस्पात क्षेत्र में देश की स्थिति मजबूत करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। मंत्री ने भरोसा जताया कि अगले पांच दशक के लिए इस्पात मांग की गारंटी है। हम चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से अवसर छीनने में पीछे हैं



और वैश्विक बाजार में बड़ी इकाई बनने के लिए अनूठी पहल करने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि इस्पात उद्योग पिछले 3-4 साल में संकट से बाहर आ गया है और वृद्धि की दिशा में बढ़ने की स्थिति में है।

इस्पात, ऐल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क से स्थानीय धातु उद्योग पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा इस्पात और ऐल्युमीनियम पर बहुत अधिक शुल्क लगाने के फैसले से घरेलू धातु उद्योग पर असर पड़ सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने आठ अक्टूबर, 2018 को इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत और ऐल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया था। एसोचैम के ग्लोबल टैरिफ वार: इम्पलिकेशन्स एंड चैलेंजेज शीर्षक से प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका के संघीय कानून, 1962 की धारा 232 के तहत ऐल्युमीनियम और इस्पात पर क्रमशः 10 और 25 फीसदी तक का शुल्क लगाने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, इस बात का आकलन मुश्किल होगा कि इस्पात और ऐल्युमीनियम पर शुल्क लगाए जाने का क्या असर होगा लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजार में अन्य देशों की तुलना में अधिक महंगे और अप्रतिस्पर्धी हो सकते हैं एवं खासकर ऐसे देशों के मुकाबले जिनके खिलाफ अमेरिका ने शुल्क नहीं लगाए हैं। इसके अलावा इसका असर जिक और निकेल की कीमत पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका दुनिया में इस्पात का सबसे अधिक आयात करता है। पिछले साल उसने 3.56 करोड़ टन इस्पात का आयात किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा चीन के विभिन्न उत्पादों पर शुल्क जड़ने के बाद इस्पात और ऐल्युमीनियम के निर्यात पर शुल्क लगा देने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक कारोबार संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का चलन तेजी से बढ़ा है।

इस्पात और एल्युमीनियम पर बहुत अधिक शुल्क लगाने से धातु उद्योग पर असर : एसोचैम

इस्पात पर शुल्क से उद्योग होगा प्रभावित

एजेंसी ■ नई दिल्ली

अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमीनियम पर बहुत अधिक शुल्क लगाने के फैसले से घरेलू धातु उद्योग पर असर पड़ सकता है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आठ अक्टूबर, 2017 को इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया था। एसोचैम के ग्लोबल टैरिफ वार: इम्प्लिकेशन्स एंड चैलेंजेज शीर्षक से प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका के संघीय कानून, 1962 की धारा 232 के तहत एल्युमीनियम और इस्पात पर क्रमशः 10 और 25 फीसदी तक का शुल्क लगाने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, इस बात का आकलन मुश्किल होगा कि इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क लगाए

सार्वजनिक इस्पात कंपनियों को करना होगा निजी इकाइयों का अनुकरण: इस्पात मंत्री

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि इस्पात क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में उभरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी कंपनियों की गतिविधियों का अनुकरण करना होगा। देश में कुल घरेलू उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 80 से 82 प्रतिशत है। इस्पात मंत्री ने स्टील क्षेत्र में एक वैश्विक इकाई के रूप में उभरने के



लिए चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से अवसर छीनने का भी आह्वान

जाने का क्या असर होगा लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्यात अमेरिकी बाजार में अन्य देशों की तुलना में अधिक महंगे और

अप्रतिस्पर्धी हो सकते हैं एवं खासकर ऐसे देशों के मुकाबले जिनके खिलाफ अमेरिका ने शुल्क नहीं लगाए हैं। इसके अलावा इसका असर जिंक और

किया। हाल में हुई बैठक में सिंह के हवाले से ब्योरे में कहा, सार्वजनिक उपक्रमों का इस्पात उत्पादन में योगदान 18 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में उन्हें निजी क्षेत्र से सीखने की जरूरत है जिनका उत्पादन में 80 से 82 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत और प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में उभरना है, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र की कंपनी से सीखना होगा।

निकेल की कीमत पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका दुनिया में इस्पात का सबसे अधिक आयात करता है। पिछले साल उसने 3.56

करोड़ टन इस्पात का आयात किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा चीन के विभिन्न उत्पादों पर शुल्क जड़ने के बाद इस्पात और एल्युमीनियम के निर्यात पर शुल्क लगा देने से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक कारोबार संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का चलन तेजी से बढ़ी है और सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के खिलाफ शुल्क लगा रही हैं। उसमें कहा गया है कि इस प्रवृत्ति के और तेज होने एवं वैश्विक आर्थिक विकास के अवरूद्ध हो जाने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत सहित अन्य विकासशील देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि इस्पात निर्यात पर अमेरिका द्वारा 25 फीसदी शुल्क लगाए जाने से घरेलू बाजार परेशान और प्रभावित हो सकता है।